भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1249
गुरुवार, 05 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग

1249. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसरो द्वारा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों और देशों के साथ मिलकर किए जा रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संवर्धन हेतु स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी निवेश और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी की उन्नति में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहकार्यों के संदर्भ में इसरो का दृष्टिकोण क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) वर्तमान में 61 देशों और 5 बहुपक्षीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र उपग्रह सुदूर संवेदन, उपग्रह नौवहन, उपग्रह संचार, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहीय अन्वेषण एवं क्षमता निर्माण हैं।

(ख) एवं (ग)

सरकार ने भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा प्रौद्योगिकी विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

i. अंतरिक्ष क्षेत्र को उदार बनाया गया है और निजी क्षेत्र को आद्योपांत अंतरिक्ष गतिविधियाँ आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

ii. अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्राधिकृत करने और उनका निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष विभाग में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन किया गया था।

iii. सरकार ने एक संपन्न अंतरिक्ष परितंत्र बनाने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियामक निश्चितता प्रदान करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 का गठन किया है।

iv. निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और उन्हें ठोस सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इन-स्पेस द्वारा बीज निधि योजना, मूल्य निर्धारण सहायता नीति, परामर्श सहायता, तकनीकी केंद्र, एनजीई के लिए डिजाइन लैब, अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास, इसरो सुविधा उपयोग सहायता, एनजीई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरिक्ष परितंत्र के सभी हितधारकों से जुड़ने के लिए इन-स्पेस के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का सृजन आदि जैसी विभिन्न योजनाओं की भी घोषणा की गई और उन्हें कार्यान्वित किया गया।

v. आज की तारीख में स्पेस स्टार्ट-अप्स की संख्या वर्ष 2014 में 1 से बढ़कर लगभग 266 हो गई है।

vi. गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) द्वारा परिकल्पित अंतरिक्ष प्रणालियों और अनुप्रयोगों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इन-स्पेस ने ऐसी गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) के साथ लगभग 71 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे प्रमोचन यान और उपग्रहों के निर्माण में उद्योग की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

vii. भारतीय एनजीई की विदेशी पूंजी तक पहुंच को आसान बनाने हेतु भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए संशोधित एफडीआई नीति जारी की है।

viii. इन-स्पेस द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय दृष्टिकोण और रणनीति की भी घोषणा की गई है, जिससे समग्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

ix. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी (वीसी) निधि की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

x. इन-स्पेस ने सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत भू प्रेक्षण (ईओ) प्रणाली की स्थापना शुरू की है। गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई है।

xi. भारतीय कंपनियों को लघु उपग्रह प्रमोचन यान (एसएसएलवी) से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है और चुने गए बोली लगाने वालों से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है।

xii. एनजीई को भारतीय कक्षीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इन-स्पेस द्वारा अवसर की घोषणा की गई है। बोली विचाराधीन है।

(घ) इसरो अपने कार्यक्रम संबंधी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने, अंतरिक्ष विज्ञान और भू प्रेक्षण डेटाबेस में वृद्धि करने, भू-केंद्र नेटवर्क का विस्तार करने, संयुक्त प्रयोगों के माध्यम से उत्पादों तथा सेवाओं को बेहतर बनाने एवं विशेषज्ञता के प्रवाह हेतु मंच स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्यों से अंतरराष्ट्रीय सहकार्य कर रहा है।

***